परीक्षा लेने वाले कब तक फेल होंगे

यहां स्कैन करें

हरिवंश चतुर्वेदी | महानिदेशक, आईआईएलएमबीएस

नीट पेपर लीक से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के संचालन पर फिर प्रश्नचिह्न लग गया है। क्या हम कभी अपनी परीक्षा प्रणाली को अभेद्य किले की तरह मजबूत बना पाएंगे?

मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए इसी 3 मई को नीट (यूजी) परीक्षा हुई थी, जिसमें देश के लगभग 22.79 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। पेपर लीक होने के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और जल्द ही नई परीक्षा कराने का वादा भी किया है। इस प्रकरण ने मेडिकल, इंजीनियरिंग व सीयूईटी की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के संचालन पर एक बार फिर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। क्या हम कभी अपनी परीक्षा प्रणाली को एक अभेद्य किले की तरह मजबूत बना पाएंगे कि कभी पेपर लीक न हो और छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े?

यह स्वाभाविक है कि जब मेडिकल (नीट) और इंजीनियरिंग (जेईई) की परीक्षाओं में पेपर लीक होने की कोई घटना घटती है या फिर उनको लेकर कोई अफवाह भी फैलती है, तो युवा वर्ग में तीखी प्रतिक्रिया होती है। ऐसी घटनाएं हमारी प्रवेश परीक्षा प्रणाली में अनास्था और अविश्वास पैदा करती हैं। उन 22.79 लाख परीक्षार्थियों की मनःस्थिति के बारे में सोचिए, जो 3 मई को देश के 551 और विदेश के 14 शहरों के 5,400 केंद्रों पर पहुंचे थे।

जैसे कि ब्योरे हैं, राजस्थान पुलिस को इस बात की शिकायत मिली थी कि नीट परीक्षा से 42 घंटे पहले वाट्सएप पर एक गेस पेपर को वितरित होते देखा गया, जिसमें बहुवैकल्पिक 410 प्रश्न और उत्तर दिए हुए थे। इस गेस पेपर के 100 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए सवालों से हूबहू मिलते पाए गए हैं। पुलिस की जांच से मालूम पड़ा कि इन 100 प्रश्नों को हल करने से कुल 720 में से 600 अंकों का जुगाड़ हो जाता है।

राजस्थान का कोटा शहर जेईई कोचिंग के अत्यधिक व्यवसायीकरण और किशोर छात्रों की आत्महत्याओं के कारण चर्चाओं में आता रहा है, लेकिन नीट के प्रश्नपत्र को लीक करने वाले गेस पेपर की कहानी राजस्थान के चुरु और सीकर जैसे शहरों से

शुरू हुई, जहां गेस पेपर को पांच लाख से तीस हजार रुपये तक में बिकते हुए देखा गया। गौरतलब है, वर्ष 2024 में भी नीट की परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने का प्रकरण सामने आया था, जिसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी असंतोष देखने को मिली। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी।

साल 2017 से पहले तक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं का संचालन सीबीएसई, एआईसीटीई और यूजीसी द्वारा किया जाता था। साल 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्रोग्राम और कार्यक्रम 1992 में प्रभाव में आया, उसमें विविध प्रकार की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी बनाने की सिफारिश की गई थी। इसी के अनुरूप साल 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई। 2024 में नीट परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण के बाद एनटीए के नेतृत्व में बदलाव के साथ-साथ हरेक स्तर पर टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा पेपर लीक को रोकने के इंतजाम किए गए थे।

राजस्थान पुलिस द्वारा नीट परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत दर्ज किए जाने के बाद एनटीए ने एक वक्तव्य जारी करके मीडिया को उन तमाम इंतजामों की विस्तार से जानकारी दी थी कि तय प्रोटोकॉल के अनुसार इस बार पेपर लीक न हो पाने के पुख्ता प्रबंध किए गए थे और हरेक स्तर पर जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी सर्विलांस और 5जी जैमर्स के प्रयोग किए गए थे। फिर भी नीट का पेपर लीक हो गया। साल 2024 में नीट पेपर की खुली बिक्री बिहार में पाई गई थी और अब राजस्थान में यही बात पाई गई है।

ऐसे में, सवाल उठना लाजिमी है। आखिर क्या कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठित एनटीए जैसी एजेंसी के तमाम प्रयासों के बावजूद फिर नीट का पेपर लीक हो गया? क्या एनटीए के पुख्ता प्रोटोकॉल को भी पेपर लीक करने वाली ताकतों ने नाकामयाब नहीं कर दिया? क्या यह हमारी राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए एक गंभीर सबक नहीं होना चाहिए कि अब नीट, जेईई और सीयूईटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के संचालन का कोई ऐसा नया मॉडल ढूंढ़ा जाए, जिसमें बहु-वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ जांच प्रणाली के मौजूदा जोखिम से छुटकारा मिल सके?

दुनिया के कई बड़े देशों में उच्च शिक्षा व पेशेवर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। छोटी-मोटी परेशानियां सभी देशों में देखी जाती हैं, मगर हमारे देश जैसी पेपर लीक की दुस्साहसिक घाटनाएं शायद ही अमेरिका, चीन और यूरोप में देखने को मिलें?

उच्च शिक्षा व आबादी के मामले में भारत और चीन, दोनों लगभग बराबर की स्थिति में हैं। चीन में 'गाओकाओ' नामक राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें 1.3 से 1.5 करोड़ परीक्षार्थी भाग लेते हैं। साल 2025 में 1.34 करोड़ परीक्षार्थियों ने इसमें भाग लिया था। जिन दिनों पूरे चीन में गाओकाओ परीक्षाएं होती हैं, उन दिनों वहां रेल, बसों और हवाई यात्राओं में रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होता है। क्या चीन की इस सबसे विशाल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं? वहां अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, हालांकि छोटी-मोटी कमियां और गड़बड़ियां देखी गई हैं। इस परीक्षा में कोई व्यक्ति किसी कदाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसे सात वर्षों की न्यूनतम सजा दी जाती है। दूसरे, चीन में भी आधुनिक टेक्नोलॉजी और एआई के उपयोग से पेपर लीक की सभी आशंकाओं को रोका जाता है।

निस्संदेह, रद्द परीक्षा जल्द ही आयोजित कर ली जाएगी, क्योंकि प्रवेश परीक्षाएं हमारी युवा पीढ़ी को अपना भविष्य बनाने का अवसर देती हैं। इन प्रवेश परीक्षाओं में सीट हासिल करना आसान नहीं होता। मुश्किल से पांच से दस प्रतिशत परीक्षार्थी कामयाबी के निकट पहुंच पाते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि बेईमानी और धन द्वारा इनमें सीट हासिल करने का कारोबार कई दशकों से जारी है? ठगों, दलालों और बिचौलियों का एक वर्ग हर साल करोड़ों रुपये की कमाई करके मासूम किशोरों और उनके परिवार को लूटते रहते हैं? क्या एक ऐसी परीक्षा प्रणाली नहीं तलाशी जा सकती, जिसमें कम से कम पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)